



Case No. 78/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-4201/JH/275/2025-RO-RNC/RU-IV

श्री शशि प्रकाश सिंह

उपायुक्त,

जिला - हजारीबाग,

नवाबगंज,

झारखंड 825301

Email Id: [dc-haz@nic.in](mailto:dc-haz@nic.in)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 08/10/2025 को 13:50 HRS, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

## मामलों का संदर्भ :-

संदर्भ 1

- (ii) अभ्यावेदक श्री मंटु सोनी उर्फ शनि कांत, पिता श्री राजेश कुमार -, ग्राम बड़कागांव -, जिला कोयला खनन परियोजना के लिए " से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखंड) हजारीबाग - FOREST CLEARANCE लेने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गलत फर्जी तरीके से ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी करने के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने " के संबंध में।
- (iii) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार पत्र सं वनभूमि विविध - 02/2025-2339 व0प0 दिनांक 07.07.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 30/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer  
National Commission for Scheduled Tribes  
Government of India  
Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003



मोहर

Copy to: - NIC for uploading